



माझीय:- राजस्व मॉडल मध्य प्रदेश ~~मो 00000000~~ ग्वालियर मो प्रो

राठ पुनरीक्षण संख्या/- R 278-II/13

1/- बृजलाल कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
 2/- सुन्नी कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
 निवासीयान कंचनपुरा सतगुंवा तहसील लिधौरा जिला
 टीकमगढ़ मो प्रो ----- पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1/- महिला पूजा कुशवाहा पति लखमन कुशवाहा
 2/- महिला सोमवती कुशवाहा पति परमानंद कुशवाहा
 निवासीयान कंचनपुरा सतगुंवा तहसील लिधौरा जिला
 टीकमगढ़ मो प्रो ----- अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मो प्रो भू 0 राठ सं 0
 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार लिधौरा
 जिला टीकमगढ़ मो प्रो दिनांक 19-11-2012 जो कि प्रकरण
 क्रमांक 3/अ-12/2012-013 मे पारित किया गया ।

Dehate
 21/04/13

श्री. *मि. ड. चव्हाण*
 द्वारा आज दि. 21.11.12 को
 राजस्व मॉडल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षणकर्तागण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये है कि अनावेदकगण ने भूमिखसरा नम्बर 4011/1, 4013/1 का सीमांकन व नापतौल करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर सीमांकन की कार्यवाही की गयी और भूमि खसरा नम्बर 4011/1 की भूमि के अंशभाग 0-200 पर आवेदक पुनरीक्षण कर्ता का कब्जा पाया जाना बताया गया सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा नक्शा फोल्डबुक सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लिधौरा के समक्ष पेश किया गया जिस सीमांकन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19-11-012 को स्वीकृत कर दिया गया है इसी आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका विधितम्मत निराकरण हेतु पेश की जा रही है :-

आधार

1/- यह कि विद्वान तहसीलदार महोदय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि

46

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-278-दो/2013

जिला-टीकमगढ़

बृजलाल कुशवाह व अन्य विरुद्ध महिला फूला कुशवाहा व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-11-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	

(आर.के. जैन) 3/5/19
सदस्य